प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक

संस्थापक स्व. श्री ठाकुरदासजी खुजनेरी

मालव समाचार

इंदौर | ■ वर्ष : 61 ■ अंक 04 ■ 30 दिसंबर 2024 ■ पृष्ठ-12 ■ मूल्य - 3.00

प्रकाशन के 6 दशक

‘लाडली बहना’ ने सालभर में बनवाई 8 राज्यों की सरकार

पॉलिटिकल पार्टियों को जीत का नया और अचूक फॉर्मूला मिल गया है। इसमें हर 10 में से 9 बार जीत की गारंटी है। फॉर्मूला है- चुनाव से पहले महिलाओं के लिए ‘लाडली बहना’ जैसी कैश स्कीम्स। महाराष्ट्र चुनाव ताजा उदाहरण है। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 48 में से 18, यानी 37% सीटें मिली थीं। ‘माझी लाडकी बहिन’ योजना लागू कर गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में 288 में से 230, यानी 80% सीटें जीत लीं। एक साल, यानी नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें 9 में ‘लाडली बहना’ जैसी स्कीम लागू की गई या वादा किया गया। इनमें से 8 राज्यों में योजना कारगर रही।

89% स्ट्राइक रेट; 1.5 लाख करोड़ की स्कीम्स, फायदा देने वाली पार्टियों के 33% विधायक बढ़े, केजरीवाल भी अब इसी राह पर

लाड़ली बहना जैसी स्कीम ने 4 राज्यों में सरकार बनवाई, 4 में पलटी

महिलाओं की कैश स्कीम जीत का फॉर्मूला क्यों है? विशेष रिपोर्ट पेज-6-7-8-9

देश की बड़ी नदी परियोजनाओं के पीछे बाबा साहेब का विजन: पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का हुआ शिलान्यास पेज- 3

सागर जिले में वर्चस्व की जंग! पेज- 2

2025 के चुनाव से पहले राजद-कांग्रेस में मनमुटाव?

लालू को लग गई थी कांग्रेस के प्लान ‘पीके’ की भनक! इसीलिए चल दिया अपना सबसे बड़ा दांव ‘एम’ पेज- 10

कांग्रेस पार्टी में फिर उठी बदलाव की आवाज

हरियाणा-महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर, यूपी की तर्ज पर क्या दूसरे राज्यों में एक्शन लेगा पार्टी नेतृत्व पेज- 05

भारतीय क्रिकेट टीम में आत्मविश्वास और सामंजस्य की कमी

अब परिवर्तन का समय

डॉ राजेश खुजनेरी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से पेज-11 पर

उम्मीद ना कर इस दुनिया में हमदर्दी की गालिब,
बड़े प्यार से दर्द देते हैं ये शिद्दत से चाहने वाले।

सागर जिले में वर्चस्व की जंग!

भूपेंद्र सिंह ने कहा...
एक मंत्री भाजपा खत्म करने में लगा

मंत्री राजपूत बोले...
एक विधायक क्या पार्टी से बड़ा हो गया

भोपाल। कुलीनों के कुनबे में इस समय सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन सागर जिले में दो नेताओं के वर्चस्व की जंग से पार्टी की साख पर दाग लग रहा है। पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह हाथ धोकर पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पूर्व मंत्री पर हमलावर हैं। दोनों कद्दावर नेताओं के बीच चल रहे शीतयुद्ध से पार्टी की साख गिर रही है। गौरतलब है कि सागर जिले के दो सीनियर विधायकों में इस समय कोल्ड वार चल रहा है। अनुशासन की सीमाओं को तोड़कर यह विवाद अब मीडिया में आ गया है। आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला खुलकर जारी है। जिन दो नेताओं में कोल्डवार चल रहा है उनमें एक हैं पूर्व मंत्री और विधायक भूपेन्द्र सिंह और दूसरे हैं प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद राजपूत। भूपेन्द्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया था कि कुछ लोग सागर में भाजपा को खत्म करने में लगे हैं। इनमें एक मंत्री भी है। इस पर गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार करते हुए कहा कि एक व्यक्ति खुद को पार्टी से बड़ा समझ रहा है। शीर्ष नेतृत्व इसे देख रहा है।

मेरी किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई भाजपा के कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। गोपाल भार्गव और मैंने सागर जिले में पार्टी को खड़ा किया है।

भूपेंद्र सिंह
पूर्व मंत्री

मैं एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन, मैंने अखबार में पढ़ा कि सागर के एक विधायक ने टिप्पणी की है है। मैं बीजेपी की 3 कठिन सीमाएं पार कर चुका हूं।

गोविंद सिहं राजपूत
पूर्व मंत्री

सागर जिले में बीजेपी में चल रही खींचतान सड़क पर आ गई है। पूर्व मंत्री और खुरई से विधायक भूपेन्द्र सिंह के बयान पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है। उन्होंने भूपेन्द्र सिंह का नाम लिए बिना कहा- एक व्यक्ति क्या पार्टी से बड़ा हो गया है? पार्टी नेतृत्व इसे देख रहा है। मैं भाजपा की तीन कठिन सीमाएं पार कर चुका हूं।भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि एक मंत्री सागर में भाजपा को खत्म करने में लगा हुआ है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ने कहा कि ऐसे लोगों को हम स्वीकार नहीं कर सकते। जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए थे। वे लोग अब हमारी पार्टी में आकर फिर से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक और कई बार मंत्री रह चुके बुंदेलखंड से आने वाले भूपेन्द्र सिंह सरकार व संगठन से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी गिनती न केवल बुंदेलखंड बल्कि, प्रदेश के बड़े भाजपा नेताओं में होती है। ऐसे में उनके द्वारा जिस तरह से मोर्चा खोला गया है, उसके मायने अब राजनैतिक बीथिका में निकाले जा रहे हैं। दरअसल, जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार रही और वे विधायक बन कर आए तो उन्हें मंत्रिमंडल में जरूर शामिल किया गया है, लेकिन इस बार ऐसा नही हुआ है, बल्कि सरकार में उनके धुर विरोधी और सागर जिले के ही दल बदलकर आने वाले गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बना दिया गया है। जिले से वे एक मात्र मंत्री हैं, सो स्वाभाविक है कि जिला प्रशासन भी उनकी बात मानता है। ऐसे में माना जा रहा है कि भूपेन्द्र सिंह की स्थानीय स्तर पर प्रशासन में पूछ परख कम हो चुकी है। इसकी वजह से उन्हें नाराज बताया जा रहा है। उनकी यह नाराजगी विधानसभा के पहले ही दिन ध्यानाकर्षण के रुप में दिखाई दी। ध्यानाकर्षण सूचना में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरा।

दो लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए: भूपेन्द्र सिंह

भूपेंद्र सिंह ने गत दिवस मीडिया से चर्चा में कहा था कि कुछ लोग सागर में भाजपा को खत्म करने में लगे है। इसमें एक मंत्री भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम स्वीकार नहीं कर सकते, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए थे। वे लोग अब हमारी पार्टी में आकर फिर से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। सिंह ने कहा ये मामला सागर जिले का है, वहां दो लोगों को लेकर मेरी आपत्ति पहले भी थी और आज भी है। सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार इन्हीं दो लोगों ने किए हैं। ये कौन दो लोग हैं। इसकी जानकारी सभी को है। प्रशासन उनकी बात सुन रहा है जो कांग्रेस से आए हैं। प्रशासन को पता है कि कब किसकी सुनना है। प्रशासन जिनके इशारे पर काम कर रहा है, वे नहीं चाहते कि भाजपा के मूल कार्यकर्ता मजबूत हों। वे तो कांग्रेस के लोगों को ही मजबूत कर रहे हैं। वे खुद भाजपा में कब तक रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा इस मामले में दिए गए बयान को भी आपत्तिजनक बताया था। भाजपा में चल रही खींचतान पर पूर्व मंत्री और राधौगढ़, विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है। अगर भूपेंद्र सिंह जैसे परिपक्व नेता जो प्रदेश के गृहमंत्री रह चुके हैं, नगरीय विकास मंत्री रह चुके हैं, वे अगर इस प्रकार का बयान वीडी शर्मा के खिलाफ दे रहे हैं तो कहीं न कहीं भाजपा में सब-कुछ ठीक नहीं है। अब देखते हैं वीडी शर्मा में भूपेन्द्र सिंह के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत है या नहीं। हालांकि यह मेरा दायित्व नहीं है मैं दूसरी पार्टी में हूं, लेकिन इतनी बड़ी और कठोर बात कहना अध्यक्ष जी के बारे में। मैं तो ये कहूंगा कि या तो अध्यक्ष जी कमजोर हो गए है, या उनके पास नियंत्रण नहीं है।खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने मीडिया से कहा- वीडी शर्मा को पार्टी में आए हुए 5 से 7 साल हुए हैं, वे इससे पहले एबीवीपी में? काम करते थे। उनका बयान घोर आपत्तिजनक है। मैंने उनकी अध्यक्षीय गरिमा का ध्यान रखते हुए प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। चाहता तो मैं भी जवाब दे सकता था।

कांग्रेस एमएलए बोले-
भूपेंद्र पर कार्रवाई करके दिखाएं वीडी

बीजेपी में चल रही खींचतान पर पूर्व मंत्री और राघौगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा- अब देखते हैं वीडी शर्मा में भूपेन्द्र सिंह पर कार्रवाई करने की हिम्मत है या नहीं ? हालांकि यह मेरा दायित्व नहीं है, मैं दूसरी पार्टी में हूं। लेकिन इतनी बड़ी और कठोर बात कहना अध्यक्ष जी के बारे में... मैं तो ये कहूंगा कि या तो अध्यक्ष जी कमजोर हो गए हैं, उनके पास नियंत्रण नहीं है।

मंत्री राजपूत बोले...
एक विधायक क्या पार्टी से बड़ा हो गया

भूपेंद्र सिंह के बयान पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उनका नाम लिए बिना कहा- भाजपा से मैं पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और 41000 वोट से जीता। दूसरा विधानसभा का चुनाव भाजपा से लड़ा और जीता। तीसरा चुनाव लोकसभा का हुआ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मेरी विधानसभा में 86000 वोटों से जीती। तो मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूं।दूसरी बात जब मैं भाजपा में आया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भाजपा मैंने जॉइन की थी। प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व उस समय मौजूद था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व के जॉइनिंग कराने पर भाजपा में आया। उस समय से लगातार मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। पार्टी को मजबूत कर रहा हूं।मंत्री राजपूत ने कहा- सागर के एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। यहां प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने टिप्पणी की, कि प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले, (5 साल पहले) ही विद्यार्थी परिषद से आए हैं, उन्हें समझ नहीं है। विद्यार्थी परिषद से तो अमित शाह भी आए हैं, विद्यार्थी परिषद से नड्डा जी आए हैं, जहां तक मैंने सुना है कि राजनाथ सिंह भी विद्यार्थी परिषद से आए हैं।राजपूत ने कहा- आप विद्यार्थी परिषद से आए व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दे रहे हो। कहने का मतलब यह है कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। ऐसे व्यक्ति को पार्टी और शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया, पार्टी नेतृत्व ने जॉइन कराया

कांग्रेसियों को बीजेपी में लाने के सवाल पर मंत्री राजपूत ने कहा- कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया। जब चुनाव हो रहे थे तो पार्टी के एजेंडे में था कि दूसरे दल के नेताओं को पार्टी से जोड़ना है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सदस्यता दूसरी पार्टी के व्यक्तियों ने की, उसमें कांग्रेस के व्यक्ति भी शामिल थे। जो इस विधानसभा चुनाव में शामिल हुए। उसमें मध्य प्रदेश के जैसे अन्य विधायक शामिल हुए ऐसे ही सागर के पूर्व विधायक भी शामिल हुए थे तो उन्हें मैंने शामिल नहीं किया। वो तो पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने किया। लेकिन जो व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व से ऊपर हो गया हो यह प्रश्न विचारणीय है।

देश की बड़ी नदी परियोजनाओं के पीछे बाबा साहेब का विजन: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का हुआ शिलान्यास

खजुराहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने देश की बड़ी नदी परियोजनाओं का श्रेय डॉ. भीमराव अंबेडकर को देते हुए कहा आजादी के बाद की जल घाटी परियोजनाओं के पीछे उन्हीं का विजन था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को कई अन्य सौगातें भी दीं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया । इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 'आज सुखद दिन है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा वह पूरा हो रहा है। जब भी सूखे की बात आती थी तो बुंदेलखंड की चर्चा होती थी। यहां से लोग बड़ी संख्या में पलायन करते थे।

पीएम मोदी ने विपक्षी दल कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहां उसकी सरकार है वहां सुशासन हो ही नहीं सकता। इसे बुंदेलखंड के लोगों ने भी वर्षों तक भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसान, माता-बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने जल संकट के स्थाई समाधान के बारे में सोचा ही नहीं, इसको समझा ही नहीं।उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जल संरक्षण का क्रेडिट एक ही व्यक्ति को देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। देश की जल शक्ति, जल संसाधन, पानी के लिए बांधों के निर्माण का किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाता है तो वह डॉ. भीमराव अंबेडकर हैं। जल घाटी परियोजनाओं के पीछे उन्हीं का विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है इसके पीछे भी बाबा साहेब के ही प्रयास थे। कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहेब को श्रेय नहीं दिया।

कांग्रेस की सरकारें घोषणाएं करने में माहिर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अतीत में कांग्रेस की सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थीं। घोषणाएं करना, फीता काटना, दीया जलाना, अखबार में तस्वीर छपने पर उनका काम वहीं पूरा हो जाता था और उसका फायदा लोगों को कभी नहीं मिल पाता था । उन्होंने कहा, 'कांग्रेस की सरकारों की न तो नीयत थी और न ही उनमें योजनाओं को लागू करने की क्षमता। आज किसान सम्मान निधि जैसी योजना का लाभ हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को किसान सम्मान निधि के 12 हजार रुपये मिल रहे हैं।' स्थानीय सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, 'आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। लोगों ने यहां के सूखे पर प्रलाप किया और राजनीतिक पर्यटन करने आए। मगर आज सौगात मिल रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, उसे पूरा किया जा रहा है। अब यह बुंदेलखंड हरा-भरा और समृद्ध बुंदेलखंड होगा।'

सुशासन भाजपा सरकार की पहचान

प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि यह पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। मध्य प्रदेश में 1,100 अटल ग्राम सुशासन भवन का भूमि पूजन किया गया है। सुशासन भाजपा सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश में जितनी सरकारें हैं उनका मूल्यांकन होना चाहिए। जहां कांग्रेस की सरकार होती है, वहां क्या काम होता है; जहां लेफ्ट वालों ने सरकार बनाई, वहां क्या हुआ; जहां परिवारवादी पार्टी ने सरकार चलाई वहां क्या हुआ; जहां मिली-जुली सरकार चली, वहां क्या हुआ; और जहां-जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला वहां क्या हुआ, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए।

सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना नैतिक दायित्व

उन्होंने दावा किया कि जब-जब भाजपा को सेवा करने का अवसर मिला, 'हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनहित के जन कल्याण, विकास के कामों में सफलता पाई है' । निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए तो देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन-रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया उनका रक्त बेकार न जाए, हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। सुशासन के लिए अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें अच्छी तरह लागू करना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा, यह सुशासन का पैमाना होता है।

सीएम मोहन यादव के भाषण की कई बड़ी बातें

'पीएम मोदी आधुनिक भारत के भागीरथ'

मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में आयोजित केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास में बोलते हुए कहा, आज का दिन भारत ही नहीं दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज पीएम नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश की धरती पर पधारे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे गंगा को धरती पर लाया गया था, वैसे ही नदी जोड़कर मोदी जी आधुनिक भारत के भागीरथ बन गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भाषण के मुख्य बिंदु

- आज का दिन भारत ही नहीं दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज पीएम नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश की धरती पर पधारे हैं।
- जैसे गंगा को धरती पर लाया गया था, वैसे ही नदी जोड़कर मोदी आधुनिक भारत के भागीरथ बन गए हैं।
- मध्यप्रदेश में जब भी सूखे की खबर आती थी, तो बुंदेलखंड का नाम सबसे पहले जहन में आता था। लोग अपने घरों के गेट निकालकर उन्हें ईंटों के पैक करके रोजगार की तलाश में घर छोड़कर चले जाते थे। बड़ा कष्ट होता था कि हमारा ये क्षेत्र सालों तक सूखे का दंश झेलता रहा।
- कांग्रेस के लोग आते थे, सूखा दूर करने के लिए बड़े-बड़े वादे करते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन नदी जोड़ो परियोजना से 10 जिलों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। चंबल नहर परियोजना से भी किसानों को लाभ मिलेगा।
- प्रदेश में नवीन ऊर्जा के लिए ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर परियोजना का शुभारंभ हो रहा है।
- कांग्रेसियों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमिपूजन कार्यक्रम और लोकार्पण सुहा नहीं रहा है। उनकी मति मारी गई है।
- हमारी सरकार के एक साल पूरे होने पर 11 दिसंबर से एक महीने तक जनकल्याण पर्व की शुरुआत की है। इस दौरान पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। जनता के हित के लिए घर-घर जाकर अभियान चलेगा।
- आज श्रद्धेय अटलजी की 100वीं जयंती है। उनकी जन्मस्थली ग्वालियर में आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है।
- प्रदेश में शासकीय पदों पर भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। मध्यप्रदेश के अलग-अलग शहरों में छह रिजनल इन्वेस्टमेंट समिट की जा चुकी है।
- हमारी सरकार ने साल 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा वह हुआ पूरा ...मुख्यमंत्री मोहन यादव

खजुराहो में आयोजित केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम की शुरूआत में पीएम मोदी का स्वागत मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया। वहीं, अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का भगीरथ बताया ।इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ' आज सुखद दिन है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा वह पूरा हो रहा है ।अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा, इसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के 10 जिलों में पेयजल, साढ़े 8 लाख खेतों को सिंचाई और उद्योग-धंधों को पानी मिलेगा ।सीएम ने कहा- हम एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने वाले हैं। पांच साल के अंदर हम ढाई लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करेंगे। जब भी सूखे की बात आती थी तो बुंदेलखंड की चर्चा होती थी। यहां से लोग बड़ी संख्या में पलायन करते थे।

मालव 50 समाचार

पिघली अवरोध की बर्फ

यह हकीकत है कि चीन भौगोलिक रूप से हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। ऐसे में जरूरी है कि तमाम विसंगतियों के बावजूद अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा के साथ पड़ोसी से रिश्ते बेहतर बनाए जाएं। लंबी खटास व तनातनी के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में हुई हालिया बैठक के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। बीजिंग में डोभाल व वांग तथा दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक निश्चित रूप से कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण प्रगति कही जा सकती है। खासकर 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद पांच वर्षों में यह पहली बातचीत, दो एशियाई दिग्गजों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण व सतर्क बदलाव को ही दर्शाती है। दरअसल, इस चर्चा का केंद्र लद्दाख पर अक्तूबर 2024 के समझौते का कार्यान्वयन था। यह सुखद ही है कि दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति बनाये रखने की प्रतिबद्धता जतायी। निश्चय ही यह कदम भविष्य में संघर्षों को रोकने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में सीमा व्यापार बढ़ाने, सीमा पार नदियों का डेटा साझा करने तथा कैलाश मानसरोवर की यात्रा को फिर से शुरू करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहन करने के उद्देश्य से छह सत्री सहमति पर भी जोर दिया गया। हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की सहमति से सारी चुनौतियां एकदम खत्म हो चुकी हैं। निर्विवाद रूप से सीमा विवाद एक संवेदनशील व जटिल मुद्दा बना है जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आपसी विश्वास में व्याप्त कमी को दूर किया जाए। निश्चित रूप से व्यावहारिक कूटनीति के साथ विश्वास निर्माण के उपायों को कदम दर कदम बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इन प्रतिबद्धताओं को अमलीजामा पहनाने के लिये सतर्कता के साथ और राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी।

बहरहाल, खट्टे-मीठे रिश्तों और लंबी कटुताओं के बावजूद इस बैठक के निहितार्थों को व्यापक संदर्भों में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निर्विवाद रूप से चीन आज दूसरी बड़ी वैश्विक शक्ति है। भारत ने भी आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है। इसके बावजूद दोनों ही देश वैश्विक शक्ति की बदलती गतिशीलता से जूझ रहे हैं। खासकर अमेरिका में होने जा रहे राजनीतिक परिवर्तन से उबरने वाली आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर। ऐसे में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को दोनों देशों की एकजुटता प्रभावित करने की क्षमता रखती है। खासकर व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों में सहयोगात्मक पहल से क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। निस्संदेह, दोनों देशों की सीमा पर शांति की पहल एक शुरुआत मात्र है। इसके उपरांत दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क, व्यापार बाधाओं व असंतुलन को दूर करना वक्त की जरूरत है। हमें सांस्कृतिक सहयोग के जरिये दोनों देशों के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का लाभ उठाना चाहिए। विश्वास कायम करने और संघर्ष की छाया दूर करने के लिये ऐसे सकारात्मक कदम जरूरी हैं। निस्संदेह, रिश्तों को सामान्य बनाने का रास्ता लंबा है, लेकिन सार्थक संवाद से अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की आशा लगातार बनी रहती है। भारत और चीन के लिये शांति सिर्फ एक आदर्श मात्र नहीं बल्कि एक अपरिहार्य आवश्यकता है। निस्संदेह, भारत और चीन के बीच हुई यह तेईसवीं मुलाकात नई उम्मीद जगाती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच यह बातचीत कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद लिए गए फैसले के अनुरूप ही हुई है। जिसमें सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की बहाली और सीमा विवाद का उचित समाधान तलाशने पर सहमति बनी थी। उम्मीद की जानी चाहिये कि संक्रमण के दौर से गुजर रहे वैश्विक परिदृश्य में भारत व चीन एकजुट होकर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यह स्थिति दोनों देशों के हित में ही कही जाएगी।

आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ा संविधान पर चर्चा का सत्र

ललित गर्ग

सर्वोच्च लोकतांत्रिक सदन लोकसभा संजीदा बहस की जगह हंगामे का केंद्र बनती जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण है। जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक बहस की जगह शोर शराबा, हंगामा और सदन का स्थगित होना ही आम होता जा रहा है। यही बात लोकसभा में संविधान को लेकर हुई दो दिनों की बहस की चर्चा के दौरान देखने को मिली। संविधान निर्माण के 75वें वर्ष पर हुई यह चर्चा भी छिछालेदार, आरोप-प्रत्यारोप एवं उच्छृंखलता का माध्यम बनी, जबकि संविधान पर इस चर्चा से जनता को एवं देश को सही दिशा मिलनी चाहिए थी, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दोहरायी जानी चाहिए थी। संविधान जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक बहस न होना लोकतंत्र को कमजोर करने एवं लोकतंत्र रूपी उजालों पर कालिख पोतना ही है। सत्तापक्ष और विपक्ष ने संविधान पर चर्चा के बहाने एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने का काम करके आकाश पर पैबंद लगाने एवं सछिद्र नाव पर सवार होकर संविधान रूपी सागर की यात्रा करने का ही संकेत देकर देश की जनता को निराश ही किया है।

भले ही अपने तर्कों एवं तथ्यों से पक्ष एवं विपक्ष ने अतीत के प्रसंगों और विषयों को अधिक रेखांकित किया गया हो। निश्चित ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग-अलग नजरियों को स्पष्ट करने वाली यह बहस न केवल समकालीन राजनीतिक मुद्दों पर बल्कि लोकतंत्र, समाज और इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने वाली रही, लेकिन इस बहस में आरक्षण, सावरकर, मनुस्मृति और अदाणी को शामिल करना विपक्ष की बुद्धि का दिवालियापन ही कहा जा सकता है। इनमें से अनेक प्रसंग और विषय ऐसे थे, जिन पर पहले भी किसी न किसी बहाने संसद के भीतर या बाहर चर्चा होती रही है। यह पहले से दिख रहा था कि विपक्ष संविधान पर चर्चा के बहाने यह बताने की कोशिश करेगा कि संविधान खतरे में है। लेकिन यह समझाने के लिए विपक्षी नेताओं के पास कोई मजबूत तर्क नहीं थे, वे यह स्पष्ट करने में विफल रहे कि आखिर संविधान को खतरा कैसे है? कांग्रेस संविधान पर चर्चा करते समय यह भी भूल गई कि वह यदि मोदी सरकार के एक दशक के कार्यकाल की गलतियां गिनायेगी तो उसे भी अपने चार दशकों के कार्यकाल की गलतियों हिसाब देना होगा। संविधान पर चर्चा के दौरान जैसे विपक्ष ने सत्तापक्ष पर आरोपों की झड़ी लगाई वैसे ही सत्तापक्ष ने भी विपक्ष पर आरोपों की बौछार की। लेकिन यह सब करते हुए पक्ष एवं विपक्ष ने संविधान की विशेषताओं को उजागर करने की सकारात्मकता की बजाय विध्वंसात्मक नीति का ही सहारा लिया।

जहां विपक्ष ने आरक्षण विरोधी आरोपों को दोहराते हुए कहा कि सत्ता पक्ष मूल रूप से आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है और जब-तब दबे-छुपे ढंग से उसकी यह अंदरूनी इच्छा संघ और पार्टी के छोटे-बड़े नेताओं के बयानों से जाहिर होती रहती है। जवाब में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की जो व्यवस्था अभी लागू है, उनकी सरकार उस पर आंच नहीं आने देगी, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई भी कोशिश वह सफल नहीं होने देगी। जाहिर है, इसमें मतदाताओं को अपनी पाली में करने की दोनों पक्षों की कोशिश भी देखी और पहचानी जा सकती है। सत्तापक्ष और विपक्ष ने संविधान पर चर्चा के बहाने एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने का काम ईर्ष्या और मात्सर्य की भावना से किया, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास को ही बल दे रहा था। लगता है कि विपक्षी नेता यह समझने को तैयार नहीं कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने संविधान के खतरे में होने का जो हौवा खड़ा किया था, वह अब असरकारी नहीं रह गया है। विपक्ष के रवैये से यही लगा कि उसे यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल हो रही है कि जाति जनगणना कराने-न कराने से संविधान की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? कांग्रेस के लिये यदि जाति जनगणना इतनी ही आवश्यक है तो नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्यों नहीं कराई गई? अच्छा होता कि कांग्रेस नेता पहले इस प्रश्न का जवाब देते और फिर जाति जनगणना की आवश्यकता रेखांकित करते। लेकिन विपक्ष एवं विशेषकर कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद ही निरुत्तर होती रही है।

पूरी बहस में महापुरुषों को घसीटने का बिंदु ऐसा था जो न केवल बहस का जायका बिगाड़ने वाला कहा जा सकता है बल्कि यह निरुद्देश्यता एवं स्तरहीनता को ही दर्शाने वाला कहा जा सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह भी बताना चाहिए कि संविधान पर बहस करते समय सावरकर का नाम लेना और मनुस्मृति दिखाना क्यों आवश्यक हो गया था? कांग्रेस को यह समझ आ जाए तो बेहतर कि सावरकर, मनुस्मृति और अदाणी का उल्लेख करते रहने से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू-तू मैं-मैं चलती रहती है, लेकिन इसमें महापुरुषों को घसीटना अब बंद होना चाहिए। हमारे हर महापुरुष ने अपने समय, समाज और समझ की सीमाओं में रहते हुए कुछ ऐसा योगदान किया, जिसके लिए हम कृतज्ञ महसूस करते हैं। इसका मतलब उनके हर विचार से सहमति रखना या उनके हर कृत्य को समर्थन देना नहीं है। लेकिन उनके प्रति समाज की या उसके एक हिस्से की भी भावनाओं का सम्मान हमारी राजनीति का हिस्सा होना चाहिए।

सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी का पुराना आरोप भी उछला, लेकिन नई बात यह रही कि इस पर बचाव की मुद्रा अपनाने के बजाय कांग्रेस इस तर्क के साथ सामने आई है कि भाजपा को भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यहां इमरजेंसी जैसी कोई भाजपा की गलती बताने में कांग्रेस नाकाम ही रही। एक और बड़ी विडम्बना यह देखने को मिली कि संविधान निर्माण को किसी दल विशेष की देन कहा गया जबकि संविधान निर्माण में सभी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर विशेषतौर पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि पिछले कुछ वर्षों से देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है, जबकि वास्तविकता यह है कि संविधान के निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका रही है जिसे पूरी तरह से नकार दिया गया। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था, वह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि वह जनआकांक्षाओं का प्रतिबिंब था। उन्होंने कहा कि संविधान पार्टी विशेष नहीं बल्कि राष्ट्र का है, पार्टी विशेष ने संविधान निर्माण को हाईजैक कर लिया।

निश्चित ही संविधान देश का सुरक्षा कवच है। लोकसभा में संविधान पर बहस की मूल आवश्यकता उन कारणों पर बुनियादी चर्चा की थी जिनके चलते संविधान निर्माताओं के सपने अभी भी अधूरे हैं और नियम-कानूनों पर संविधान की मूल भावना के अनुरूप पालन नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, इसमें शक नहीं कि बहस का केंद्र यही सवाल रहा कि कौन संविधान और संवैधानिक मूल्यों को लेकर समर्पित है और कौन इस पर दोहरा खेल खेल रहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां सावरकर के सहारे भाजपा पर निशाना साधा वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की गलतियां गिनाईं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान के रूप में मिले सुरक्षा कवच को तोड़ा है। भारत का संविधान, संघ का विधान नहीं है। इसी बात को दोहराते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो देश एवं दुनिया भलीभांति देख रही है। मोदी के शासन में न केवल देश के भीतर शांति एवं अमनचैन बना है बल्कि सीमाओं पर भी सुरक्षा मजबूत हुई है। पडोसी देश भारत की ओर नजर करने का दुस्साहस नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अधिक सीमा की सुरक्षा एवं देश की सुरक्षा क्या हो सकती है? उचित होता संविधान पर चर्चा के दौरान बहस के स्तर को ऊंचा उठाते हुए आरोप-प्रत्यारोप से बचते हुए संविधान को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायक बनने वाले बिंदुओं पर सहमति कायम की जाती।

कांग्रेस पार्टी में फिर उठी बदलाव की आवाज

हरियाणा-महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर,यूपी की तर्ज पर क्या दूसरे राज्यों में एक्शन लेगा पार्टी नेतृत्व

कांग्रेस के जी-23 समूह ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बड़े निर्णय नहीं लिए गए तो विकल्प तलाशे जाएंगे

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। लगातार पार्टी संगठन में फेरबदल की मांग उठ रही हैं। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व न केवल माथापच्ची में जुटा है, बल्कि एक्शन भी शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। 6 दिसंबर को ही पार्टी ने यूपी की राज्य, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कमेटियों को भंग करने को स्वीकृति दी। इस कदम को बड़े संगठनात्मक बदलाव के नजरिए से देखा जा रहा है। चर्चा ये भी है कि कई दूसरे राज्यों में भी जरूरी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर चुकी है। पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं।140वां स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण मौका है, जो कांग्रेस के पुनर्निर्माण और नई दिशा तय करने की शुरुआत हो सकता है।

कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जब 99 सीटें जीतकर आई तो ये ऐसा लगा कि पार्टी एक बार फिर वापसी की राह पर है। हालांकि, चंद महीनों में ही दो राज्यों में करारी शिकस्त ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी। उत्तर भारत में पार्टी की स्थिति कमजोर नजर आ रही। चर्चा ये भी है कि अहमद पटेल जैसे नेता की कमी पार्टी को खल रही है। अब देखना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इन कमियों को दूर करने और देश की सबसे पुरानी पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं?

बदलाव का ब्लूप्रिंट जल्द पेश करने की तैयारी

कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव की आवाज पिछले कई महीनों से उठ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इस बारे में पहले भी कई मौकों पर संकेत दिया है लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब पार्टी के अंदर से बदलाव की आवाज जोर-शोर से उठने लगी है। तुरंत अगर बदलाव नहीं हुआ तो एक बार फिर से पार्टी का पुराना सिरदर्द जी-23 समूह सक्रिय हो सकता है। हालांकि इस बार इस जी-23 में दूसरे नेता होंगे।इन नेताओं का आरोप है कि पार्टी के अंदर फैसले नहीं होने से वर्करों में अब बेचैनी होने लगी है। नेताओं का यह समूह पार्टी को चेतावनी दे रहा है कि अगर अब बड़े फैसले नहीं लिए गए, तो ये वर्कर अपने लिए नया विकल्प तलाशना शुरू कर देंगे। ऐसा हुआ तो पार्टी के लिए आगे की राह और कठिन हो जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व को भी इसका अहसास होने लगा है और वह बदलाव का ब्लूप्रिंट जल्द पेश करने की तैयारी में है। दरअसल, बदलाव की सारी प्रक्रिया एक अहम पद पर आकर रुक जा रही है। पार्टी के इस सबसे अहम पद पर किस तरह का बदलाव हो और किसे वहां रखा जाए, यही चुनौती इसमें सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

कैसे संगठन को फिर मजबूत करेगा पार्टी नेतृत्व

कांग्रेस के सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई की बैठक में खरगे ने अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी के लोग अपने स्तर पर अनुशासन में बंधें। उन्होंने कांग्रेस की एक और बड़ी कमी की ओर इशारा किया था कि पार्टी अपने पक्ष के माहौल को नहीं भुना पाती। इस तरह खरगे ने संगठन की कमजोरियों को तो स्वीकार किया लेकिन एक्शन प्लान क्या रहेगा अब ये देखना बाकी है।

बदलाव की दिशा में संभावित कदम

- **प्रदेश इकाइयों का पुनर्गठन:** राज्य इकाइयों में नए नेतृत्व को लाने और कमेटियों को भंग करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- **युवा चेहरों को मौका:** संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए युवाओं और नए चेहरों को प्रमुख भूमिकाएं सौंपी जा सकती हैं।
- **प्रभारी और अध्यक्षों में बदलाव:** महाराष्ट्र और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को बदले जाने की संभावना है।

पार्टी अब कुछ नए प्रयोग तलाश रही है जिसमें

1. **युवाओं को जिम्मेदारी:** युवा नेताओं को प्रमुख भूमिकाओं में लाकर पार्टी को नई दिशा दी जा सकती है।
2. **जमीनी स्तर पर काम:** कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद और जमीनी स्तर पर काम करने की प्राथमिकता जरूरी है।
3. **नेतृत्व का सशक्तिकरण:** पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत और स्पष्ट रणनीति अपनाने की जरूरत है।

नई किताब, नया सिरदर्द

कांग्रेस को नई किताबें अक्सर सिरदर्द देती रही हैं। पार्टी के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर अपनी किताब के साथ सामने आए, जिसमें उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। हालांकि उनके सवालों की कोई खास चर्चा नहीं हो पाई। पार्टी को उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी किताब में ऐसे सवाल उठाएंगे। अब चर्चा है कि पार्टी के एक और सीनियर नेता अपनी किताब लेकर आ रहे हैं। उसमें काफी राजनीतिक मसाला होने की बात कही जा रही है। पार्टी नेतृत्व किताब का कंटेंट पता लगाने की कोशिश कर रहा है।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे किताब लेकर आ गए थे। इसमें उन्होंने ऐसी बात लिख दी, जिससे बीजेपी को कश्मीर में कांग्रेस पर हमला करने का पूरा मसाला मिल गया। 2014 में भी पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के सलाहकार की लिखी किताब ने राजनीतिक बवाल मचा दिया था और उससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। कांग्रेस के एक नेता ने इस ट्रेंड पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी इसलिए अपने नेताओं को लिखने की अनुमति नहीं देती है।

कौन बोले कौन नहीं

संविधान पर लोकसभा में हुई चर्चा में कांग्रेस की ओर से कौन-कौन स्पीकर भाग लेंगे, इस बारे में पार्टी में अंतिम समय तक दुविधा रही। सबसे बड़ी दुविधा तो इस बात को लेकर थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, दोनों संविधान पर हो रही इस बहस में भाग लें या नहीं। एक वर्ग का मानना था कि एक बहस में दोनों का भाषण न हो। लेकिन दूसरा तर्क यह आया कि बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब तकरीबन हर बहस में भाग लेंगे, ऐसे में इस आधार पर प्रियंका गांधी को दूर रखना सही नहीं होगा। जाहिर है, दूसरे तर्क की जीत हुई और आखिरकार प्रियंका गांधी को बहस में उतारा गया।

यूपी में कमिटियां भंग, क्या दूसरे राज्यों में भी होगा एक्शन

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस अध्यक्ष राज्य इकाइयों में अहम बदलाव करते हुए नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटियों को भंग किया गया है। वैसे ही अन्य राज्यों में भी बदलाव की संभावना है। महाराष्ट्र भी उन राज्यों में शामिल है जहां नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कई राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और समितियों को भंग किया जा सकता है। नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर संगठन में नई ऊर्जा भरने की कवायद हो सकती है।

दुविधा में सांसद

इन दिनों दो क्षेत्रीय दलों के सांसदों के अगले कदम को लेकर बहुत चर्चा है। एक पार्टी के राज्यसभा सांसदों के बारे में लोकसभा चुनाव के बाद से उलझन है, तो दूसरी पार्टी के लोकसभा सांसदों के बारे में हालिया विधानसभा चुनाव के बाद उलझन बन गई है। इनके बारे में तरह-तरह की चर्चाएं उठ रही हैं और दबे स्वरों में कहा जा रहा है कि मौका मिलने पर वे पाला बदल सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं उठने के बाद इन दोनों दलों के नेतृत्व के भी कान खड़े हो चुके हैं। संसद सत्र के दौरान दोनों दलों के सांसदों को हमेशा एक साथ दिखाने की कोशिश की गई। वे किसी न किसी बहाने उन्हें एक साथ सामने लाया जाता रहा, जिससे संदेश जा सके कि सब साथ हैं और टूट की खबर बेबुनियाद है। लेकिन अंदरखाने की चर्चा के अनुसार ऊपर से भले ही सब ठीक-ठाक दिखाया जा रहा हो, टूट की बात में दम है। दोनों दलों के सांसद अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं और वे अपने लिए तमाम विकल्प टटोल रहे हैं।

‘लाडली बहना’ ने सालभर में बनवाई 8 राज्यों की सरकार

89% स्ट्राइक रेट; 1.5 लाख करोड़ की स्कीम्स, फायदा देने वाली पार्टियों के 33% विधायक बढ़े, केजरीवाल भी अब इसी राह पर

पॉलिटिकल पार्टियों को जीत का नया और अचूक फॉर्मूला मिल गया है। इसमें हर 10 में से 9 बार जीत की गारंटी है। फॉर्मूला है- चुनाव से पहले महिलाओं के लिए ‘लाडली बहना’ जैसी कैश स्कीम्स। महाराष्ट्र चुनाव ताजा उदाहरण है। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 48 में से 18, यानी 37% सीटें मिली थीं। ‘माझी लाडकी बहिन’ योजना लागू कर गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में 288 में से 230, यानी 80% सीटें जीत लीं। एक साल, यानी नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें 9 में ‘लाडली बहना’ जैसी स्कीम लागू की गई या वादा किया गया। इनमें से 8 राज्यों में योजना कारगर रही। स्ट्राइक रेट 89%। लोकसभा चुनाव पहले दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 8 राज्यों राह पर चलते हुए केजरीवाल भी अब लाड़ली बहन वाली स्कीम लेकर आए हैं। किसी भी राज्य में सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में है। मध्यप्रदेश में ऐन चुनाव के पहले लागू की गई लाड़ली बहना योजना ने सबसे पहले ये साबित किया। मध्यप्रदेश के चुनाव नतीजे ऐसी नज़ीर बने, जिसके बाद असम से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु और ओडिशा तक महिलाओं की कैश ट्रांसफर स्कीम के जरिए पार्टियां सत्ता की राह मजबूत करती रही हैं। ताज़ा मामला दिल्ली का है, जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव से ठीक दो महीने पहले मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लांच कर दी।

मध्यप्रदेश

चुनाव से 240 दिन पहले 6 किस्तें पहुंचीं, नतीजों में ‘प्रो इन्कम्बेंसी’ दिखी

मध्यप्रदेश

योजना का नाम	मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना
कितनी महिलाओं को फायदा	1.2 करोड़+
हर महीने कितनी रकम	1250 रुपए
योजना का कुल बजट	करीब 19 हजार करोड़ सालाना

2023 में महिलाओं का वोट प्रतिशत: 76% (+2%)

2023 में बीजेपी का वोट प्रतिशत: 48.6% (+7%)

2023 में बीजेपी के विधायकों की संख्या: 163 (+54) (0 – 230 सीटें)

महिलाओं को हर महीने कैश देने की स्कीम की चर्चा मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई। 15 मार्च 2023 को चुनाव से 8 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च किया। 10 जून 2023 को इसकी पहली किस्त जारी हुई थी। चुनाव से पहले कुल 6 किस्तें प्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते में पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश सरकार सालाना इस योजना पर 19 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च करती है। ये खर्च मध्य प्रदेश के कुल बजट का करीब 5% है।लाड़ली योजना के लागू होने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में रिकॉर्ड 76% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था।

2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में 31 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट किए।

चुनावी सर्वे कराने वाली पोलस्टार कंसल्टिंग फर्म के मुताबिक मध्य प्रदेश चुनाव में कुल महिलाओं के वोट में से करीब 50% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। बीजेपी को मिलने वाला वोट कांग्रेस की तुलना में 10% ज्यादा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर अदिति नारायण पासवान के मुताबिक कास्ट और रिलीजन की तरह अब वोटिंग पैटर्न जेंडर के आधार पर शिफ्ट हो गया है। जब आप महिलाओं को कुछ सुविधाएं देते हैं, तो वे घर से निकलकर वोट डालने आती हैं। पहले महिलाओं को उनके पति बताते थे कि उन्हें किसे वोट करना है। 2023 में 15 साल के एंटी इन्कम्बेंसी के बावजूद मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीतने की सबसे बड़ी वजह लाड़ली बहना योजना है।

महिलाओं की कैश स्कीम जीत का फॉर्मूला क्यों है पेज - 8 पर

केजरीवाल भी लाए ‘लाडली बहना’ वाली स्कीम, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए पेज - 9 पर

छत्तीसगढ़

चुनाव से बीजेपी ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया, पलट गया खेल

छत्तीसगढ़

योजना का नाम	महतारी वंदन योजना (बीजेपी ने वादा किया)
कितनी महिलाओं को फायदा	70 लाख+
हर महीने कितनी रकम	1000
योजना का कुल बजट	करीब 4,900 करोड़ सालाना

2023 में महिलाओं का वोट प्रतिशत: 76.2% (-0.1%)

2023 में बीजेपी का वोट प्रतिशत: 46.3% (+13%)

2023 में बीजेपी के विधायकों की संख्या: 54 (+39) (0 – 90 सीटें)

2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कमोबेश सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई गई थी लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी ने बाजी पलट दी। दरअसल, बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में सीधे 1000 रुपए प्रतिमाह भेजने का वादा किया। इसके लिए फॉर्म भी भरवाने शुरू कर दिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जब तक इस वादे की गंभीरता को समझ पाते देर हो चुकी थी। बघेल ने भी दोबारा से कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 15000 देने का ऐलान किया था। साथ ही महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का ऐलान किया।

महिलाओं ने देखा कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में पैसे मिलने शुरू हो चुके हैं, तो बीजेपी के वादे पर ही भरोसा किया।राज्य की करीब 76% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ये 2018 की तुलना में 11 लाख ज्यादा था। महिलाओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक रहा।चुनाव के बाद 10 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लॉन्च किया। 70 लाख महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए भेजना शुरू किया गया।अर्थशास्त्री अभय तिलक एक इंटरव्यू में बताते हैं कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश इन राज्यों में महिलाओं की एक बड़ी संख्या ऐसी है, जिसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। परिवार में उनके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन ऐसी योजनाओं से इन महिलाओं को कुछ पैसे मिल रहे हैं और उनके परिवारों में उनकी स्थिति सुधर रही है। यही वजह है कि महिलाएं उनके खाते में सीधे पैसा भेजने वाले राजनीतिक दलों को वोट करने के लिए घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जा रही हैं।

महाराष्ट्र

चुनाव से पहले 7500 खाते में पहुंचे, महायुति को 80 सीटें मिलीं

महाराष्ट्र

योजना का नाम	माझी लाडकी बहिन योजना
कितनी महिलाओं को फायदा	2.34 करोड़
हर महीने कितनी रकम	1500 रुपए
योजना का कुल बजट	46 हजार करोड़ सालाना

2024 में महिलाओं का वोट प्रतिशत: 65.2% (+6%)

2024 में बीजेपी+ का वोट प्रतिशत: 48.16%

2024 में बीजेपी+ के विधायकों की संख्या: 230 (+50) (0 – 288 सीटें)

2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का महायुति गठबंधन सिर्फ 37% सीटें जीत सका। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक करीबी नेता बताते हैं कि ‘साहेब’ ने कहा हम भी मध्य प्रदेश जैसी लाड़ली बहना योजना लाएंगे। वित्त मंत्री अजित पवार बोले- खजाने में पैसा नहीं है। इसके बावजूद शिंदे अड़े रहे। उन्होंने माझी लाडकी बहिन योजना का ऐलान कर दिया। 28 जून 2024 को योजना लॉन्च हुई। 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाते हैं। सरकार ने इसके लिए 46,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसमें 200 करोड़ रुपए मार्केटिंग के लिए हैं। इसमें राज्य बजट का लगभग 7.6% खर्च हो रहा है। महाराष्ट्र की 2.34 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1500 रुपए आ रहे हैं। जुलाई 2024 से अब तक कुल पांच किस्तें आ चुकी हैं। यानी चुनाव से पहले ही महिलाओं के खातों में 7500 रुपए पहुंच गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी खुले मंच से स्वीकार करते हैं कि इस योजना ने खेल पलटा है। एकनाथ शिंदे तो अपने आप को लाड़ला भाई भी कहते हैं।दिव्य मराठी के सीनियर जर्नलिस्ट मनोज कुलकर्णी बताते हैं कि ये योजना महायुति ने बहुत अच्छे से प्लान की थी। इसका फॉर्म बेहद सिंपल था। न पैन नंबर भरना था, न कोई फॉर्म 16 जैसा कुछ। बस फॉर्म भरने वाली महिला को खुद से ये घोषणा करनी थी कि उनके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपए से कम है। 6% बढ़े हुए महिला वोटरों ने महाराष्ट्र में खेल बदल दिया। वरिष्ठ पत्रकार विनोद जैतमहाल कहते हैंमुंबई और आसपास के जिलों में महिला मतदाताओं में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 2019 से तुलना करें तो ये आंकड़ा मुंबई में 7% बढ़ा हुआ है। ठाणे 11%, पालघर में 9% महिला वोटर में बढ़ोतरी हुई है।

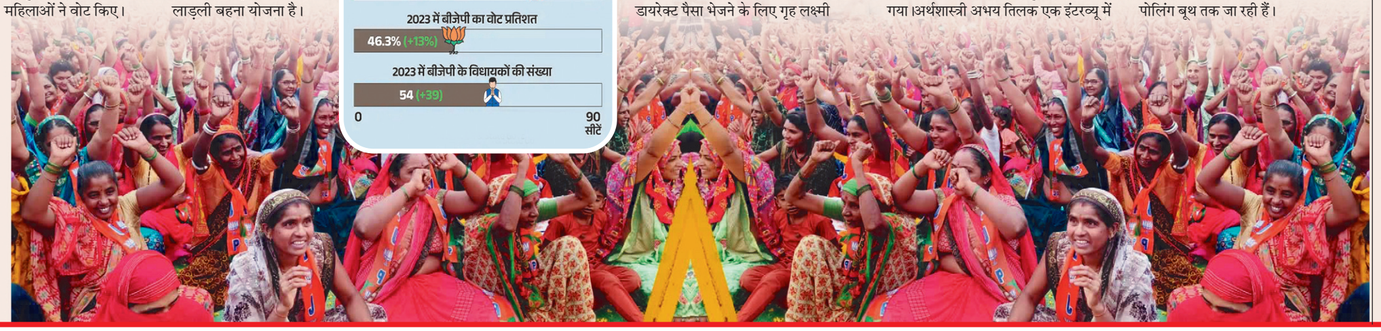

‘लाडली बहना’ जैसी स्कीम ने 4 राज्यों में सरकार बनवाई, 4 में पलटी

नवंबर 2023 से नवंबर 2024

राज्य	चुनाव कब हुए	योजना की डिटेल	योजना का इम्पैक्ट
महाराष्ट्र	नवंबर 2024	महायुति सरकार ने **‘माझी लाडकी बहिन योजना’** लागू की। चुनाव से पहले 2.34 करोड़ महिलाओं के खाते में 5 किस्तों के 7500 रु. पहुंचे। (नोट- 1500 रु. की एक किस्त)	✓ **योजना कारगर** महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीत लीं।
झारखंड	नवंबर 2024	JMM सरकार ने **‘मंइयां सम्मान योजना’** लागू की। चुनाव से पहले करीब 48 लाख महिलाओं के खाते में 4000 रुपए पहुंचे। (नोट- 1000 रु. की एक किस्त)	✓ **योजना कारगर** JMM के नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक ने 81 में से 56 सीटें जीत लीं।
हरियाणा	अक्टूबर 2024	बीजेपी सरकार ने **‘लाडो लक्ष्मी योजना’** का वादा किया। इसमें 78 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रु. दिए जाने थे।	✓ **वादा कारगर** महिलाओं ने वादे पर भरोसा जताया। 90 में से 48 सीटें बीजेपी ने जीत लीं।
आंध्रप्रदेश	मई 2024	टीडीपी के नेतृत्व वाले NDA अलायंस ने **‘सुपर-6’** के तहत 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रु. देने का वादा किया।	✓ **वादा कारगर** NDA के वादे का असर हुआ। 175 में से 164 सीटें जीत लीं।
ओडिशा	मई-जून 2024	बीजेपी ने **‘सुभद्रा योजना’** का वादा किया। इसमें महिलाओं को सालाना 10 हजार रु. देने का वादा किया गया।	✓ **वादा कारगर** 24 साल से सत्ता में काबिज बीजेडी को बीजेपी ने हरा दिया। 147 में से 78 सीटें जीत लीं।
मध्यप्रदेश	नवंबर 2023	मार्च 2023 में बीजेपी सरकार ने **‘लाड़ली बहना योजना’** शुरू की। चुनाव से पहले करीब 1.2 करोड़ महिलाओं के खाते में 11 हजार रु. पहुंचाए। (नोट- 1250 रु. की एक किस्त)	✓ **योजना कारगर** बीजेपी ने 230 में से 164 सीटें जीत लीं।
तेलंगाना	नवंबर 2023	चुनाव में कांग्रेस ने **‘महालक्ष्मी योजना’** का वादा किया। इसमें परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,500 रु., हर महिला को मुफ्त बस यात्रा और 500 रु. में गैस सिलेंडर देने का वादा किया।	✓ **वादा कारगर** कांग्रेस को 119 में से 64 सीटें जीत लीं।
छत्तीसगढ़	नवंबर 2023	बीजेपी ने **‘महतारी वंदन योजना’** का वादा किया। इसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रु. देने का वादा किया। कांग्रेस सरकार ने भी वादा किया, पर लागू नहीं किया।	✓ **वादा कारगर** 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 54 सीटें जीत लीं।
राजस्थान	नवंबर 2023	कांग्रेस ने **‘गृह लक्ष्मी योजना’** का वादा किया। इसमें परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10 हजार रु. देने की बात की, लेकिन लागू नहीं कर पाए।	✗ **वादा कारगर नहीं** कांग्रेस 199 में से 70 सीटें ही जीत सकी। बीजेपी ने 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।

नोट- इस एक साल के भीतर 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए। लेकिन यहां महिलाओं से जुड़ी कोई कैश स्कीम नहीं थी। एक राज्य में सरकार पलटी और 2 में सरकार बरकरार रही। जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद पहला चुनाव था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जीता।

महिलाओं की कैश स्कीम जीत का फॉर्मूला क्यों है?

4 पॉइंट्स में समझते हैं....

1. पैसों की इतनी तंगी कि कैश हजार-दो हजार भी बड़ी राहत

कोविड महामारी के बाद से भारतीय परिवारों की माली हालत बिगड़ी है। केंद्र सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। प्रोविडेंड फंड के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 4.45 करोड़ पीएफ क्लेम अप्रूव किए गए हैं, जो पिछले साल से 7.8% ज्यादा हैं। आमतौर पर कोई रास्ता न बचने पर ही लोग पीएफ से पैसा निकालते हैं। जून में जारी आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि लोगों की सेविंग्स में भी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 में कुल घरेलू बचत जीडीपी के 18.4% पर आ गई है, जो औसतन 20% होती थी। इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, 'देश में प्रति व्यक्ति आय करीब एक लाख रुपए सालाना है। यानी करीब 8500 रुपए महीने। अगर किसी परिवार में महिलाओं को दो हजार रुपए महीने मिल रहे हैं तो ये उस परिवार की कमाई में 25% की ग्रोथ है। इसके लिए न तो कुछ करना है और न ही किसी को घूस देनी है। एक सिंपल फॉर्म भरना है, जिसके बाद सीधे खाते में पैसे आने लगते हैं।'दिल्ली की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे बताते हैं,1500 रुपए महीने का मतलब हुआ रोजाना महज 50 रुपए। इससे पता चलता है कि भारत के ज्यादातर वोटर्स कितने गरीब हैं कि इतनी छोटी रकम से भी वे राहत महसूस करते हैं।

2. सालों से अनदेखी झेल रही महिलाएं एक नया वोटबैंक बनी

मूलोकनीति-सीएसडीएस की विभा अत्री ने भारत में महिला वोटर्स ने रिसर्च की। उनके मुताबिक, महिला वोटर्स ने अपने वोट की ताकत को समझना और विश्वास करना शुरू कर दिया है। 69% महिला वोटर्स का मानना है कि वोटिंग देश में चीजों को चलाने के तरीके में बदलाव लाती है। दिसंबर 2023 में एसबीआई-रिसर्च की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक महिलाओं की वोटिंग में 55% बढ़त हो सकती है। वहीं पुरुषों में 45% की गिरावट आ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं का वोटिंग पर्सेंटेज 65.8% रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं का वोटिंग पर्सेंटेज 65.8% रहा।अमिताभ तिवारी मानते हैं कि ऐसी योजनाओं के कारण महिलाओं को बढ़ावा मिला है। वे कहते हैं,लंबे समय से महिलाओं को अनदेखा किया जा रहा था, आज उन्हें अहमियत मिली है। अब महिलाएं परिवारों में अपनी बात मजबूत से कह पा रही हैं। इससे महिलाओं का वोटिंग पैटर्न भी बदला है।

3. बीजेपी ने 'महिला वोटबैंक' को पहचाना, इससे सत्ता विरोधी रुझान को मात दी

बीते एक साल में जिन 9 राज्यों में 'लाडली बहना' जैसा फैक्टर था, उनमें से 7 राज्यों में बीजेपी या एनडीए को फायदा मिला। केंद्र से लेकर राज्यों तक बीजेपी ने महिलाओं को पहचान देने के कई कदम उठाए। जुलाई 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने अपने बजट में महिलाओं और बच्चियों की मदद करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देने का ऐलान किया।मोदी सरकार 3.0 ने पहले 100 दिनों में 11 लाख नई 'लखपति दीदियों' को सर्टिफिकेट दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक करोड़ से ज्यादा 'लखपति दीदियां' अब हर साल एक लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% से ज्यादा घर महिलाओं को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उभरती बिजनेसविमेंस को 30 करोड़ रुपए लोन दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया है। साथ ही हायर एजुकेशन में महिलाओं के रजिस्ट्रेशन में 28% के बढ़त हुई है।अगस्त 2019 में बीजेपी की मोदी सरकार ने 'तीन तलाक' को खत्म करने के लिए कानून बनाया। ऐसा कर पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी की ओर लामबंद करने की कोशिश की।सितंबर 2023 में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। यानी 543 सीटों वाली लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिलाएं एक वोटबैंक बन चुकी हैं। ये ऐसा वोटबैंक है, जिसके पैटर्न को कोई नहीं पकड़ पा रहा। ये चुपचाप बूथ में जाती हैं और अपनी सरकार को चुनती हैं। उसे प्रचंड बहुमत दिलाती हैं।चुनावों में महिलाओं पर फोकस्ड स्कीम के गेमचेंजर होने पर अभय दुबे कहते हैं,यह दौर 'एंटी-इनकम्बेंसी' नहीं, बल्कि 'प्रो-इनकम्बेंसी' का है। सत्ता में कदम जमा चुकी पार्टियों का तख्ता पलटना मुश्किल होता जा रहा है। महाराष्ट्र- झारखंड में यही हुआ, हालांकि यह मॉडल हमेशा ही कारगर नहीं होता है।

4. आगे क्याः जब तक योजनाएं नई, तभी तक पार्टियों को फायदा

अमिताभ तिवारी बताते हैं,भारत में आज इतनी असमानता बढ़ी है कि ऐसी योजनाएं लानी पड़ रही हैं। ऐसा करने से पार्टियां अगर सरकार बना पा रही हैं तो वे ऐसा आगे भी कर सकती है। पार्टियों ने सीधा फॉर्मूला बना लिया है कि पैसा बांटने की योजनाएं लाओ और चुनाव जीतो।अभय कुमार दुबे कहते हैं, 'कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं जब तक नई होती है, तब तक वोटों में तब्दील होती रहती हैं, क्योंकि लाभार्थी मदद देने वाली सरकारी पार्टी का आभार मानते हैं। जब योजना पुरानी हो जाती है तो वे उस तत्परता से बदले में वोट नहीं देते। लोकसभा चुनाव और 2022 में यूपी चुनाव में बीजेपी इस मुश्किल का सामना कर चुकी है।'

झारखंड

वोटिंग से एक रात पहले चौथी किस्त आई, सोरेन की सत्ता में वापसी

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रक्षाबंधन के एक दिन बाद यानी 20 अगस्त 2024 को मंइयां सम्मान योजना शुरू की थी। ये योजना वोटिंग से 85 दिन पहले शुरू की गई थी। इसके तहत 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए देने का वादा किया गया। सरकार ने इसका बजट 15 हजार करोड़ रुपए रखा है जो राज्य बजट का करीब 12% है। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में 31 अगस्त को पहली किस्त आ गई थी। वहीं चुनाव से पहले चार किस्तें जा चुकी थीं। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने ये राशि बढ़ाकर 2500 रुपए करने की घोषणा कर दी।13 और 20 नवंबर को हुई वोटिंग में कुल 67.74% वोटिंग हुई। महिला वोटर्स का परसेंटेज 70% था। अगर 2019 की बात करें तो 67% महिलाओं ने वोट किया था। 81 कुल विधानसभा सीटों में से 68 सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल कहते हैं कि बीजेपी ने ज्यादा देने का वादा करके इस योजना को काटने की कोशिश की थी, लेकिन महिलाओं के खाते में चार किस्तें आ चुकी थीं। यहां वादे से ज्यादा महिलाओं ने प्रमाण पर भरोसा किया। दस-दस रुपयों की तंगी झेलने वाली आदिवासी महिलाओं के खाते में सीधे हर महीने हजार रुपए आने लगे तो उनका सरकार पर भरोसा बढ़ गया। रोजगार के मसले पर हेमंत सरकार फेल हो चुकी थी। लोगों की इनकम के सोर्स कम थे। ऐसे में हर महीने घर बैठे बिना कुछ किए एक हजार रुपए आना बड़ी बात थी। इस योजना ने महिलाओं का भरोसा जीत लिया।

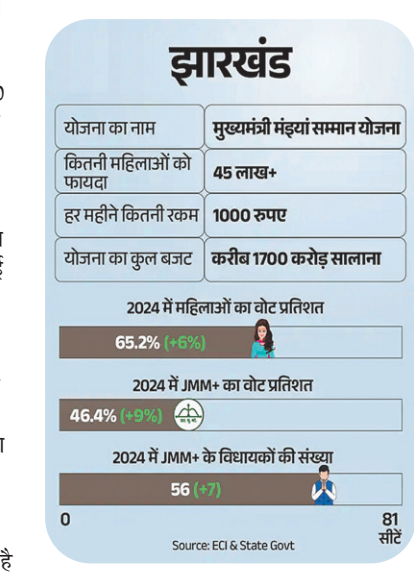

राजस्थान

अशोक गहलोत के वादे पर ऐतबार नहीं, कारगर नहीं हुई स्कीम..

नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से एक महीने पहले अक्टूबर 2023 में अशोक गहलोत ने राजस्थान के झुंझुनू में गृह लक्ष्मी गारंटी के तहत परिवार की महिला मुखिया को साल में 10 हजार रुपए देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि ये राशि दो से तीन किश्तों में दी जाएगी। कांग्रेस ने इस वादे का चुनाव प्रचार के दौरान खूब इस्तेमाल किया। महिलाओं के खाते में पैसे भेजने के सिर्फ वादे किए। चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अशोक गहलोत के वादे के बरक्श महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी तीन मुख्य योजनाएं लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना और पीएम मातृ वंदना योजना शुरू करने का वादा की। महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल भारद्वाज का कहना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने महिलाओं को हर साल 10 हजार रुपए देने का वादा किया था। हालांकि, महिलाओं को लगा कि सत्ता में रहते हुए जो सरकार महिलाओं के लिए ये योजना नहीं लागू कर पाई वो चुनाव जीतने के बाद लागू करेगी इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे में महिलाओं ने खुलकर कांग्रेस का साथ नहीं दिया और राजस्थान में सरकार पलट गई। इसी तरह हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में महिलाओं से जुड़ी कैश स्कीम एक बड़ा फैक्टर साबित हुई।

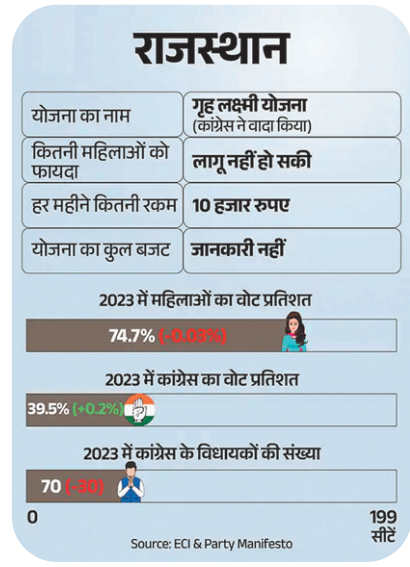

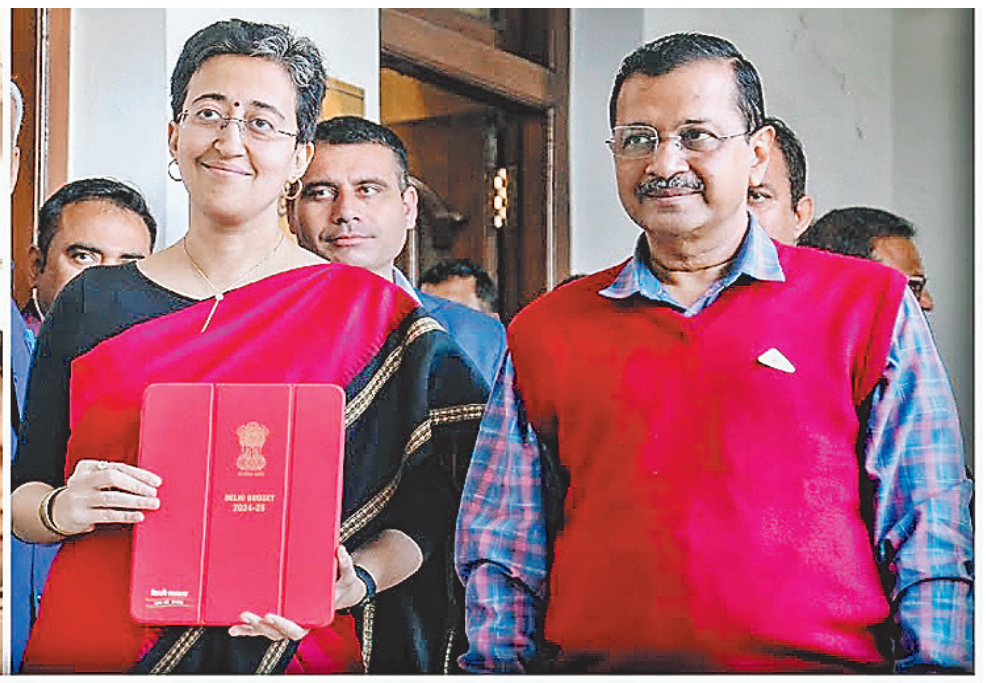

केजरीवाल भी लाए 'लाडली बहना' वाली स्कीम, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए

लोकसभा चुनाव पहले दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह पर चलते हुए केजरीवाल भी लाड़ली बहन वाली स्कीम लेकर आए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार का 10वां बजट पेश करते हुए दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है। आतिशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1 हजार रुपये दिए जाने का ऐलान किया है।आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा।केजरीवाल ने साफ किया कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों।इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटोवालों के लिए 5 लाख तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले दो महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थीं।

फ्री की हो गई शिकायत ...नोटिस पर क्लेश ...

ठंड के दिनों में दिल्ली की सियासत का तापमान हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की दो बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के दो विभागों ने अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है।पहला इश्तिहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी है।आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, ये केजरीवाल की गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्राइवेट अस्पताल में निशुल्क इलाज मिलेगा। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में दिए जाएंगे। इसमें गलत क्या है? भाजपा ने दबाव बनाकर जिन अधिकारियों से ये नोटिस निकलवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम अपनी योजना जारी रखेंगे। ताजा विवाद कथित तौर पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में नोट बांटने का है। मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर नोट बांटने का आरोप मढ़ा है।

आंध्र प्रदेश

योजना का नाम	सुपर-6 (TDP+ ने वादा किया)
कितनी महिलाओं को फायदा	जानकारी नहीं
हर महीने कितनी रकम	1500 रुपए
योजना का कुल बजट	जानकारी नहीं

2024 में महिलाओं का वोट प्रतिशत
80.3% (+1%)

2024 में TDP+ का वोट प्रतिशत
55.2%

2024 में TDP+ के विधायकों की संख्या
164 (+140)
0 — 175 सीटें

Source: ECI & Party Manifesto

तेलंगाना

योजना का नाम	महालक्ष्मी योजना (कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया)
कितनी महिलाओं को फायदा	जानकारी नहीं
हर महीने कितनी रकम	2500 रुपए
योजना का कुल बजट	जानकारी नहीं

2024 में महिलाओं का वोट प्रतिशत
71.6% (-5%)

2024 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत
39.4% (+11%)

2024 में कांग्रेस के विधायकों की संख्या
64 (+45)
0 — 119 सीटें

Source: ECI & Party Manifesto

ओडिशा

योजना का नाम	सुभद्रा योजना (बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया)
कितनी महिलाओं को फायदा	80 लाख+
हर महीने कितनी रकम	10 हजार रुपए
योजना का कुल बजट	55.8 हजार करोड़

2024 में महिलाओं का वोट प्रतिशत
75.6% (+1.5%)

2024 में बीजेपी का वोट प्रतिशत
40% (+7.6%)

2024 में बीजेपी के विधायकों की संख्या
78 (+55)
0 — 147 सीटें

Source: ECI & State Govt

हरियाणा

योजना का नाम	लाडो लक्ष्मी योजना (बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया)
कितनी महिलाओं को फायदा	95.7 लाख
हर महीने कितनी रकम	2100 रुपए
योजना का कुल बजट	करीब 24 हजार करोड़

2024 में महिलाओं का वोट प्रतिशत
66.7% (-0.3%)

2024 में बीजेपी का वोट प्रतिशत
39.9% (+3.5%)

2024 में बीजेपी के विधायकों की संख्या
48 (+8)
0 — 90 सीटें

Source: ECI & State Govt

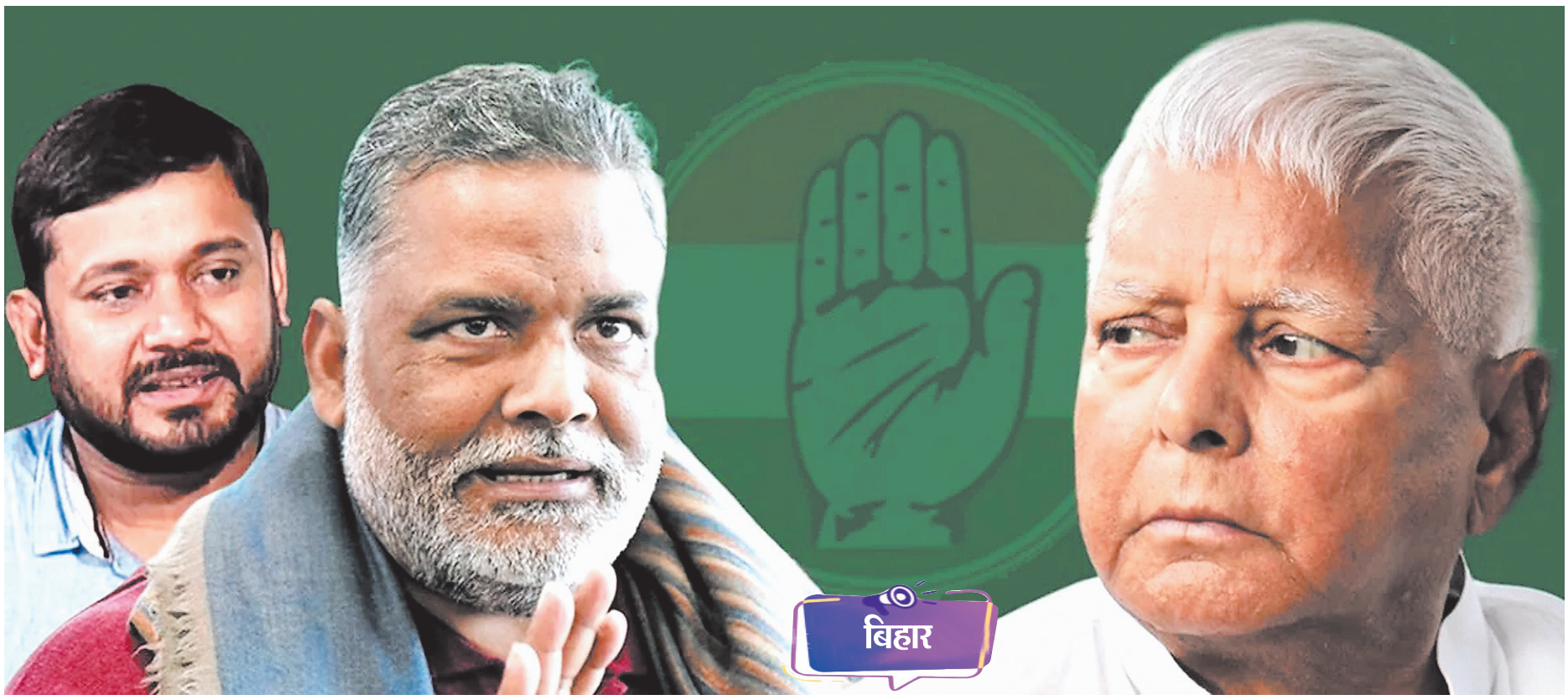

2025 के चुनाव से पहले राजद-कांग्रेस में मनमुटाव?

लालू को लग गई थी कांग्रेस के प्लान 'पीके' की भनक! इसीलिए चल दिया अपना सबसे बड़ा दांव 'एम'

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर इंडिया ब्लॉक के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने की वकालत यूं ही नहीं की है। इसके पीछे उनकी सुचिंतित चाल है। लालू को पता चल गया है कि कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में न सिर्फ सीटों के लिए अड़ेगी, बल्कि उन चेहरों को भी सामने लाएगी, जो लालू यादव को पसंद नहीं हैं। कांग्रेस की रणनीति की जैसे ही लालू को भनक मिली, उन्होंने पैंतरा बदल लिया। लालू किसी भी हाल में तेजस्वी के सामने उन 'दो चेहरों' के उभार के खिलाफ रहे हैं।

बिहार में कांग्रेस तकरीबन तीन दशक से आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। कांग्रेस का प्रदेश में नेतृत्व किसके पास रहेगा, यह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तय करते रहे हैं। लालू ने पिछले साल कांग्रेस दफ्तर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया भी था कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजने में उनकी क्या भूमिका रही। उनका दावा था कि उनके ही कहने पर सोनिया गांधी ने अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजा था।

पिछलग्गू नहीं बनेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने अब अपनी पिछलग्गू छवि बदलने का प्लान बनाया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस ने जो मंथन किया, उसमें दो बातें उभर कर सामने आई थीं। पहला यह कि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। दूसरा कि विधानसभा चुनावों में जातीय जनगणना और संविधान पर खतरा जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की बजाय पार्टी स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उत्तर प्रदेश में पार्टी की सभी इकाइयां भंग कर कांग्रेस ने इसकी शुरुआत भी कर दी है।

ये है कांग्रेस का 'प्लान पीके'

बिहार में भी कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करेगी। इतना ही नहीं, चुनाव के लिए पार्टी पहले से ही कुछ स्थानीय चेहरों को सामने लाने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस ने प्लान पीके बनाया। इस कड़ी में पहला नाम 'पी' यानी पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और दूसरा नाम 'के' यानी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार का आ रहा है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी जग जाहिर है। दोनों से लालू और तेजस्वी की अदावत सबको पता है। कन्हैया कुमार बिहार के तो हैं ही, वे बेगूसराय से संसदीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वे चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन बिहार में उनके चेहरे को लोग पसंद करते हैं। संसदीय चुनाव में कन्हैया को इसलिए कामयाबी नहीं मिल पाई थी कि आरजेडी ने भी वहां से अपना उम्मीदवार दे दिया था। तब वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के कैंडिडेट थे।

कन्हैया होंगे कांग्रेस का फेस!

कन्हैया अब कांग्रेस के साथ हैं और लंबे समय से पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं दी है। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उन्हें बिहार से आजमाने की तैयारी में थी, लेकिन लालू के दबाव में उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। आखिरकार कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली में उतारा। कन्हैया कुमार के इस बार मैदान में उतरने की भनक पाते ही लालू ने अपना तेवर सख्त कर लिया और इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। पर, कांग्रेस भी इस बार किसी दबाव में आने के मूड में नहीं है।

कांग्रेस को चाहिए 70 सीटें

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम ने तीन बातें कह कर आरजेडी के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्होंने पहली बात कही कि विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के आधार पर होगा। अब वे कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो दो उप-मुख्यमंत्री होंगे। मार्के की उनकी तीसरी बात यह थी कि इंडिया ब्लॉक में कोई छोटा-बड़ा भाई नहीं है और सीटों में कटौती कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं होगी।

पप्पू भी बदला लेने को तैयार

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने को कांग्रेस का सिपाही मानते हैं। अपनी जन अधिकार पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय इसीलिए किया था कि उन्हें पार्टी पूर्णिया से लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी। कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने उन्हें इसका आश्वासन भी दिया था। ऐन वक्त सब कुछ बदल गया। लालू-तेजस्वी ने पहले ही आरजेडी का उम्मीदवार बीमा भारती को घोषित कर दिया। हालांकि इंडिया ब्लॉक की बिहार में आरजेडी के बड़ी पार्टी होने के नाते उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से उनके आवास जाकर मुलाकात भी की थी। हद तो तब हो गई, जब तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की एक सभा में कह दिया कि आरजेडी को वोट नहीं दे सकते तो एनडीए को दे दें, लेकिन पप्पू यादव को कतई न दें। विधानसभा चुनाव में पप्पू को कांग्रेस अपना हथियार बनाएगी। उन्हें भी तेजस्वी से बदला लेने का मौका मिल जाएगा।

कन्हैया से तेजस्वी को भय

कन्हैया कुमार से तेजस्वी को भय लगता है। कन्हैया उनसे अधिक पढ़े-लिखे हैं। सांसदी का दो चुनाव लड़ चुके हैं। अपने तर्कसंगत भाषणों से कन्हैया विरोधियों पर भी कुछ देर के लिए प्रभाव छोड़ते हैं। वामपंथी पहचान तो उनकी जेएनयू के जमाने से ही रही है, अब भाजपा की धुर विरोधी कांग्रेस में रहने का भी उन्हें लाभ मिल सकता है। इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है और कन्हैया उस टीम में आते हैं तो यह तेजस्वी के लिए इसलिए खतरनाक होगा कि लोग दोनों की बातों, विचारों, तर्कों और शिक्षा की तुलना शुरू कर देंगे। यह तेजस्वी के लिए सियासी तौर पर शुभ नहीं माना जाएगा।

इसीलिए लालू का यह पैंतरा

लालू नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के चेहरे बिहार विधानसभा चुनाव में सामने रखे। उनकी यह भी कोशिश है कि कांग्रेस पहले की तरह आरजेडी की पिछलग्गू बनी रहे। इसलिए कि सीटों के बंटवारे में उनकी मर्जी चल सके। इस बार कांग्रेस को पिछली बार की तरह 70 सीटें देने के मूड में आरजेडी नहीं है। कांग्रेस 70 सीटें लेकर पिछली बार सिर्फ 19 ही जीत पाई थी, जिससे तेजस्वी उभार के बावजूद सीएम नहीं बन सके। कांग्रेस को भी सीटों में कटौती का भय सता रहा है। इसीलिए दोनों ओर से तनातनी दिख रही है। कांग्रेस लोकसभा के हालिया चुनाव के स्ट्राइक रेट के आधार पर टिकट बंटवारा चाहती है। अब तो दो डेप्युटी सीएम का भी दावा कर दिया है।

लालू के बयान पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति...

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही 'इंडिया' गठबंधन के दो दल कांग्रेस और राजद में मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी हैं। इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव के 'इंडिया' गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी के नाम पर हामी भरने के बाद से हुई है। कांग्रेस ने पहले बयान दिया था कि बिहार में कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं है। चुनाव में सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट के हिसाब से होगा। अब कांग्रेस ने इससे आगे बढ़ते हुए दो उपमुख्यमंत्री पदों की मांग रख दी है, जिसमें से एक पद मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित करने की बात कही है।इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपने का सुझाव दिया था। इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'कांग्रेस पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वजूद नहीं है, वह पूरी तरह से बेतुका है। अगर आप सिर्फ एक राज्य में मजबूत हैं तो उसके आधार पर आप दूसरे दल पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखना चाहिए।'

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार

भारतीय क्रिकेट टीम में आत्मविश्वास और सामंजस्य की कमी, अब परिवर्तन का समय

डॉ राजेश खुजनेरी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से

हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सोफिटेल होटल में मेरे प्रवास के दौरान, मुझे खिलाड़ियों को निकटता से देखने का अवसर मिला, मैदान पर और मैदान के बाहर। जो मैंने देखा वह गहरी चिंता का विषय था और टीम के भीतर एक अंतर्निहित समस्या को दर्शाता था। उनकी विश्व स्तरीय स्थिति के बावजूद, खिलाड़ी दूर, अंतर्मुखी और स्पष्ट रूप से असंतुष्ट लग रहे थे। उनमें से कई अकेले चलते या बैठते हुए देखे गए, और उनके बीच दोस्ती या सकारात्मकता का कोई संकेत नहीं था। होटल के लॉबी में, जहाँ केवल कुछ भारतीय प्रशंसक मुख्य रूप से होटल में ठहरे परिवार मौजूद थे, वहाँ कोई उत्साह या गर्माहट नहीं थी। जो प्रशंसक खिलाड़ियों से फोटो या हस्ताक्षर के लिए संपर्क करते थे, उन्हें अधिकांशतः अनादर या सीधे मना करने का सामना करना पड़ा।

उदाहरण के लिए, रोहित शर्मा फोटो के लिए पूछे जाने पर चिड़चिड़े और असभ्य नजर आए। उन्हें अक्सर अपने आईफोन से चिपके हुए देखा गया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या अत्यधिक स्क्रीन टाइम उनके रिफ्लेक्स, ध्यान और यहाँ तक कि नींद को प्रभावित कर रहा है। गौतम गंभीर हमेशा गुस्से में नजर आए, उनका व्यवहार तनावपूर्ण माहौल को और बढ़ा रहा था। बुमराह भी शांत और disengaged दिखाई दिए। खिलाड़ियों के बीच कोई स्पष्ट एकता नहीं थी। जैसे-जैसे खेल का समय बढ़ा, खिलाड़ियों जैसे जडेजा की एक बार की ऊर्जा मैदान पर गायब थी, जो टीम के भीतर आत्मविश्वास और सामंजस्य की कमी को और भी उजागर कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि केवल जेसवाल और आकाशदीप को एक साथ देखा गया, जो समग्र अलगाव के विपरीत था।

यह आंतरिक गतिशीलता के बारे में सवाल उठाता है, जहां वरिष्ठ खिलाड़ी जो एक महत्वपूर्ण समय से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा प्रतिभाओं के साथ सामंजस्य में नहीं हो सकते, जो खुद को साबित करने के लिए उत्सुक है। मैदान पर स्थिति इस तनाव को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय टीमें मैचों के दौरान मुखर, जीवंत, और ऊर्जा से भरपूर रही हैं। हालांकि, गाबा में खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और उत्साह की कमी थी, जिससे स्पष्ट आंतरिक दरार को छिपाना संभव नहीं हो सका। भारतीय क्रिकेट के लिए परिवर्तन को अपनाने का समय आ गया है। टीम में नए, युवा प्रतिभा का समावेश उनकी ऊर्जा, ध्यान, और एकता को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि अनुभव का अपना स्थान है, कम प्रदर्शन कर रहे वरिष्ठ खिलाड़ियों को पीछे हटना चाहिए ताकि नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिल सके। भारतीय क्रिकेट को एक ऐसी टीम की आवश्यकता है जो न केवल कुशल हो, बल्कि एकजुट और उत्साही भी हो—एक ऐसी टीम जो मैदान पर और मैदान के बाहर राष्ट्र को गर्वित करे।

Time for Change: Injecting Young Blood into Indian Cricket

During my recent stay at the Sofitel Hotel with the Indian cricket team, I had the opportunity to observe the players closely, both on and off the field. What I witnessed was deeply concerning and reflective of an underlying issue within the team.Despite their world-class status, the players seemed distant, withdrawn, and visibly unhappy. Many of them were seen walking or sitting alone, with no signs of camaraderie or positivity among them. The hotel lobby, where only a handful of Indian fans-primarily families staying at the hotel-were present, lacked any excitement or warmth. Fans who approached the players for photos or signatures were largely turned away, met with irritability or outright refusal.

India team manage. Dhol specialist australia go every match

Rohit Sharma, for instance, came across as irritable and rude when asked for a photo. He was often seen glued to his iPhone, raising questions about whether excessive screen time might be affecting reflexes, focus, and even sleep. Gautam Gambhir appeared perpetually angry, his demeanor adding to the tense atmosphere. Bumrah, too, seemed subdued and disengaged.There was no visible sense of unity among the players. The once-energetic field presence of players like Jadeja was noticeably absent during their match at the Gabba, further underscoring the lack of confidence and cohesion within the team.Interestingly, the only players seen together were Jaiswal and Akashdeep, a stark contrast to the overall isolation. This raises questions about internal dynamics, where senior players-who have been underperforming for a significant period-may not be in harmony with younger talents eager to prove themselves.

The situation on the field mirrored this tension. Historically, Indian teams have been vocal, animated, and brimming with energy during matches. At the Gabba, however, the players seemed to lack both confidence and enthusiasm, unable to mask the apparent internal rift.It is time for Indian cricket to embrace change. Injecting fresh, young talent into the team is crucial to reviving their energy, focus, and unity. While experience has its place, underperforming senior players should step aside to allow a new generation of athletes to take the reins.Indian cricket deserves a team that is not just skilled but also cohesive and spirited-a team that makes the nation proud both on and off the field.

Dr Rajesh khujneri
From Gabba Brisbane
Australia

एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले बन गए मुख्यमंत्री मोहन यादव

लगभग 17 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्नेह हासिल नहीं कर सके, डॉ. मोहन यादव एक साल का कार्यकाल पूरा करते ही उनकी आंखों के तारे बन गए। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रदेश में जाते हैं, वहां उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं लेकिन मोहन यादव की तारीफ दूसरे प्रदेश राजस्थान में वहां के मुख्यमंत्री के सामने हुई।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में मोदी ने मोहन यादव को लाड़ला मुख्यमंत्री कहा। अवसर था पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित करार कार्यक्रम का। इस जीवनदायिनी योजना से राजस्थान और मप्र के बड़े हिस्से में सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान होना है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की नजर में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री लाड़ले ही हैं। आखिर, दिग्गजों को दरकिनार कर एक साल पहले डॉ मोहन यादव को मप्र और भजनलाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। दोनों नाम नए थे और चौंकाने वाले भी। एक साल बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मोहन को लाड़ला कहने से साफ है कि उनका यह कार्यकाल अच्छा रहा और पार्टी नेतृत्व उनसे पूरी तरह संतुष्ट है। संभवत: इसीलिए 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री ने कभी लाड़ला नहीं कहा, जबकि एक साल बाद ही मोहन, मोदी के लाड़ले हो गए।वहीं, सीएम मोहन यादव ने पार्वती-कालीसिंध- चंबल (PKC) प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के 20 साल के इंतजार को खत्म करने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को आधुनिक युग के भगीरथ बताया है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए दोनों राज्यों को जल-शक्ति का सदा-उर्वरा आशीष मिलेगा। अकेले मध्य प्रदेश की 6.13 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई पानी मिलेगा। साथ ही लाखों लोगों की प्यास बुझेगी।बता दें कि पीएम मोदी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट के लिए 17 दिसंबर 2024 को एमओए के साथ योजना के पहले फेज की आधारशिला रखी थी। इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन आने वाले 8 साल में किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है।

सौरभ शर्मा प्रकरण में बोले दिग्विजय सिंह...

यह परिवहन घोटाला, कहा..... मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में हो जांच

मध्य प्रदेश में उजागर हुए परिवहन घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के सभी नेता मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी निष्पक्ष जाँच की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास का ये अब तक का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है।

उन्होंने कहा जंगल में खड़ी एक कार से 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी , 11 करोड़ रुपये कैश मिलना बताता है कि ये मामला कितना बड़ा है। उन्होंने कहा अब सामने आ रहा है कि किस तरह परिवहन विभाग में चेक पोस्ट की नीलामी होती थी। उन्होंने कहा एक सिपाही सौरभ शर्मा के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है, ये किसकी है इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा पास जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक पुलिस ने तो इसे दबाने का पूरा प्रयास किया था। यदि लोकायुक्त और पुलिस के बीच आयकर विभाग नहीं होता तो शायद ये घोटाला भी सामने नहीं आता।इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने इस प्रकरण में प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की भूमिका की जांच करने और सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की बात भी उठाई।दिग्विजय सिंह ने दावा करते हुए कहा जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तब उनपर इतना दबाव था कि परिवहन विभाग एक व्यक्ति विशेष को दिया जाये। पूर्व परिवहन मंत्री का नाम लेते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जैसे ही सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने उस विधायक को परिवहन विभाग दे दिया गया।दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्र लिखकर कहा कि मध्य प्रदेश का ये भ्रष्टाचार आपके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वादे के खिलाफ है। इसमें जो पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा का नाम आया है वो तो छोटी मछली है। करोड़ों की संपत्ति अकेले उसकी नहीं हो सकती। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाकर एक्शन होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने मामले की जाँच हाईकोर्ट के जज से कराने की भी मांग की।

अकल चबूतरे से

बहसबाजी के प्रसारण में मल्लयुद्ध प्रवक्ता

जैसी राजनीतिक गतिविधियां आजकल हो रही हैं, और जैसी टीवी डिबेट आजकल हो रही है, उसे देखते हुए उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ इस तरह की टीवी डिबेट हमें किसी टीवी चैनल पर दिखाई देगी-चालू चैनल में टीवी एंकर प्रचंड प्रताप सिंह आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ संसद के बाहर, अलां पार्टी के सांसद ने फलां पार्टी के सांसद को घूंसा मारकर गिरा दिया और फलां पार्टी के सांसद ने अलां पार्टी के नेता पर हमलों की बौछार कर दी।

व्यंग्य **आलोक पुराणिक**

अलां और फलां पार्टी की महिला नेत्रियों ने एक-दूसरे के बाल नोचे। जी ये देखिये वो सीन—टीवी पर नोचा-नोची, बॉक्सिंग के सीन चल रहे हैं, बैकग्राउंड में गीत बज रहा है-यह देश है वीर जवानों का।एंकर प्रचंड प्रताप सिंह= आज हमारे साथ अलां पार्टी के शारीरिक प्रवक्ता डंडा सिंह और फलां पार्टी के शारीरिक प्रवक्ता झंडा सिंह। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जैसी प्रचंड शारीरिक बहस हम करवाते हैं अपने चैनल पर वैसी बहस कहीं न हो सकती। लोग कुश्तियां देखना भूल जायेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चैनल देखना भूल जायेंगे, तो शुरू करते हैं आज की बहस, जी अलां पार्टी के नेताजी बताइये कि आपने घूंसा क्यों मारा।अलां पार्टी के शारीरिक प्रवक्ता घूंसा लहराते हुए टीवी स्क्रीन पर-पीछे से बैकग्राऊंड में गीत बज रहा है-अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं हूं मैं हूं डॉन।फलां पार्टी के शारीरिक प्रवक्ता ने जवाबी घूंसा लहराया टीवी स्क्रीन पर-पीछे से बैकग्राऊंड में गीत बज रहा है-है अगर दुश्मन जमाना, ज़माना ग़म नहीं, ग़म नहीं।एंकर प्रचंड प्रताप सिंह= देखिये दोनों नेताओं से निवेदन है कि हमारे टीवी चैनल को परिवार देखते हैं, आप गालियां न दें। गालियां दें तो संसदीय गालियां ही दें।अलां पार्टी का प्रवक्ता=देखिये गालियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है।फलां पार्टी का प्रवक्ता=देखिये, गालियां एक बार शुरू होती हैं, तो हम से नहीं रुक सकतीं।दोनों पार्टियों के प्रवक्ता कूदकर टेबल पर चढ़ जाते हैं, पहले एक-दूसरे का कुर्ता फाड़ते हैं।स्क्रीन पर मैसेज उभरता है कि यह न्यूज शो फलां नर्सिंग होम ने स्पांसर किया था, चैनल की खबरों से ज्यादा तेज इस नर्सिंग होम की एंबुलेंस।

कही-सुनी

कीर्ति राणा

संघ के शताब्दी वर्ष का घोष

आरएसएस ने शताब्दी वर्ष में भले ही कार्यक्रम नहीं करने का मन बना रखा हो किंतु नये साल में संघ का बड़ा कार्यक्रम इंदौर में हो रहा है। संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत की उपस्थिति में दशहरा मैदान में मालवा प्रांत का घोष शिविर 31 दिसंबर से शुरु होकर 3 जनवरी को एक हजार स्वयंसेवकों के घोष के साथ समाप्त होगा। इस त्रिदिवसीय घोष शिविर में 20 हजार लोग शामिल होंगे।

लापरवाही-सख्ती एक समान

होल्कर कॉलेज में रेगिंग से छात्र ने जान गवाई हो, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हर एक-दो साल में रेगिंग की घटना उजागर होती हो।रेगिंग मामले में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही सामने आती ही है। प्रशासन भी ऐसे मामलों में सख्ती तो खूब दिखाता है लेकिन कुछ महीनों में सब कुछ सामान्य हो जाता है। रेगिंग की ये घटनाएं अब तो लापरवाही-सख्ती वाली नूरा कुश्ती होती जा रही है।वैसे भी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जब डीन की कुर्सी प्रतिष्ठा का मुद्दा बन जाए तो रेगिंग मामले में कौन ध्यान देगा।

आंबेडकर-आंबेडकर-आंबेडकर

इंदिरा गांधी ने 49 साल पहले आपात्तकाल घोषित किया था। तब नईदुनिया ने संपादकीय वाला हिस्सा खाली छोड़ कर अपना मौन विरोध प्रकट किया था। अब संसद से लेकर सड़क तक चल रहे प्रदर्शनों में आंबेडकर को लेकर चल रहा विवाद गरमाया हुआ है। सांध्य दैनिक प्रभात किरण ने संपादकीय वाले स्थान पर पूरी जगह आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर लिख कर नया प्रयोग किया है।

मधुमिलन-महापौर !

नगर निगम चाहे जितने विकास कार्य कराए लेकिन मधुमिलन चौराहा पर महीनों से चल रहे विकास-निर्माण काम ने इस रोड से आने-जाने वाले रोज चकरघिन्नी होने के साथ महापौर को बड़े प्रेम से याद करते हुए आते जाते हैं।महापौर तो क्या निगम आयुक्त के पास भी जवाब नहीं है कि मधुमिलन चौराहा क्यों निगम की ढिलाई की पहचान बन गया है।

बोले...बोले, काजी साहब बोले

याकूब अली साहब के जन्नतनशीं होने के बाद उनके साहबजादे डॉ इशरत अली शहर काजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अपनी मौजूदगी का अहसास कराते रहने वाले काजी साहब ने सालों बाद चुप्पी तोड़ी है।खजराना के शासकीय उर्दू स्कूल में बोलते हुए नशा बेचने वालों पर बरसते हुए बोल पड़े आप तो मुझे इन लोगों के नाम बता दो, इनकी टांगे तोड़ना मुझे आता है। काजी साब की ये बात भाजपा वालों को भी पसंद आई होगी क्योंकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी तो नशा बेचने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है।इस अभियान में शहर काजी का खुल कर बोलना इसलिये मायने रखता है कि अल्पसंख्यक समाज के नेताओं ने तो चुप्पी साथ रखी है।

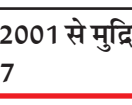

चिंटू ने दिखा दी संगठन क्षमता

भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने ग्रामीण भाजपा के 16 मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्तियां बगैर विवाद-उठापटक के आम सहमति से की है उससे यह भी साबित हो गया कि जिला संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। 16 में से 13 मंडल अध्यक्षों के नाम आम सहमति से तय हो गए। शेष बचे तीन मंडल (देपालपुर, गौतमपुरा और महू नगर) ही ऐसे रहे जहां पहले अध्यक्ष रहे फिर से रिपीट किये गये हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बस चलता तो चिंटू वर्मा को देपालपुर से विधानसभा चुनाव लड़वा देते, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनवा कर मनोज की घेराबंदी तो कर ही रखी है। लेकिन मनोज पटेल भी मनोज पटेल हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में चुनाव के दौरान कैलाशजी की सभा रास नहीं आई थी तो उनके चेले-चपाटे कैसे रास आयेंगे?

एक अकेला सब पर भारी...

पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह शायद अब भाजपा और खासकर वर्तमान परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ आग उगलना बंद कर दें।करोड़ों नकदी और चांदी-सोने के सौदागर परिवहन निरीक्षक सौरभ शर्मा की पूर्व सीएम के के जमाने में परिवहन विभाग में तूती बोलती थी। अभी तो नकदी-सोना सामने आया है। डायरियों-जमीनों की रजिस्ट्री की असलियत सामने आना बाकी है।सरकार पर निर्भर करता है कि प्याज के छिलके की तरह इस कांड की परतें खुले या नर्सिंग घोटाले की तरह इसे भी भुला दिया जाए। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव एक होने के बाद से बयानों की बम वर्षा तो करते रहे हैं लेकिन परिवहन विभाग के इस कांड के बाद भाजपा के खिलाफ और कितने दिन बोलते हैं यह अब देखना है।परिवहन विभाग के एक निरीक्षक की कमाई ने जिस तरह दिल्ली तक को चौंकाया है, उस बदनामी के छींटें कितनों के कलफ लगे कपड़े खराब करेंगे यह भी देखना है। वैसे दिग्विजय सिंह ने तो रंग में भंग कर ही दिया है कि एक परिवहन निरीक्षक को पास इतनी संपत्ति है तो डीजीपी, परिवहन मंत्री के पास कितनी होगी।दिग्विजय सिंह ने कह दिया है पूर्व सीएम के रुप में मेरी संपत्ति के साथ ही भाजपा के पूर्व सीएम की संपत्ति की भी जांच की जाए।

वाह रे वाह, जागरुक युवा...!

जो सुनेगा, हंसेगा और आश्चर्य करेगा कि देवी अहिल्या विवि की विभिन्न परीक्षाओं में इस साल डेढ़ हजार छात्र शामिल ही नहीं हो पाए। युवा सोशल मीडिया पर तो खूब एक्टिव रहते हैं लेकिन इन छात्रों को विवि की वेबसाइट देखने की फुर्सत ही नहीं मिली जिस पर परीक्षा संबंधी सूचना तो थी लेकिन ये छात्र देख ही नहीं पाए।संबंधित कॉलेजों ने भी इन छात्रों को परीक्षा संबंधी सूचना नहीं दी। अब छात्रों ने जनसुनवाई में अनुरोध किया है कि ये 15 परीक्षाएं फिर से करवाएं क्योंकि हम शामिल नहीं हो पाए थे।

ठसने की कला ?

सिंधिया के साथ भाजपा में आए, मंत्री बने एक नेताजी के हर कार्यक्रम में मंच पर ठसने की कला से भाजपा के अन्य मंत्री से लेकर वरिष्ठतम अधिकारी भी परेशान हैं लेकिन हर बार कसमसा कर रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे समझाएं। विभिन्न जिलों के कलेक्टर तो मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी स्टॉफ को अपनी परेशानी बता भी चुके हैं। अब इंतजार है कि मप्र की सरकार को संचालित करने वाले संघ-संगठन के नेता ही उन्हें अनुशासन का पाठ सुनाएं।

उच्चशिक्षा मंत्री रहते की गई मांग पूरी करेंगे सीएम

मध्य प्रदेश के कॉलेजों में बीते सात सालों से बंद पड़े छात्रसंघ चुनाव अगले शिक्षा सत्र से शुरु होते हैं तो मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम इतिहास दर्ज हो जाएगा। यही नहीं वह कहावत भी सही हो जाएगी देने वाले श्रीनाथजी, पाने वाले श्रीनाथजी। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते डॉ मोहन यादव ने छात्र संघ चुनाव संबंधी प्रस्ताव तैयार कराया था और मुख्यमंत्री चौहान को भेजा था। अब तो खुद मोहन यादव ही मुख्यमंत्री हैं। छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होने का लाभ यह कि युवा नेतृत्व के लिये राजनीति में अवसर बढ़ जाएंगे।

एक रेप में तो दूसरे जुआं कांड में उलझे

भाजपा के दो पार्षदों से उनके संरक्षक नेताओं ने भी हाथ खींच लिये हैं।कुछ समय चुप्पी वाले समझौते के बाद वही महिला फिर पार्षद नितिन उर्फ शानू शर्मा के खिलाफ मुखर हो गई है। भाजपा विधायक मालिनी गौड़ ने भी अपने हाथ खींच लिये हैं। इसी तरह खजराना क्षेत्र से पार्षद पुष्पेंद्र पाटीदार। और उनके मित्रों को एक मैरेज गार्डन में जुआं खेलते हुए पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा था। तब विधायक से लेकर महापौर तक ने पुलिस को ठंडा रहने के लिये दबाव बनाया था लेकिन इन नेताओं को जब जुआं खेलते पाटीदार मित्रमंडल का वीडियो दिखाया तो ये सारे नेता ठंडे पड़ गये। भाजपा कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि इन दोनों पर संगठन क्या एक्शन लेता है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विनोद खुजनेरी द्वारा अपना देश प्रिंटर्स से अनुबंध पर 204 शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इंदौर 452001 से मुद्रित तथा प्रकाशित।
संपादक: विनोद खुजनेरी। मोबाइल: 98270-10709। आरएनआई पंजीयन क्रमांक 13186/67